

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर 2018—भाद्रपद 23, शक 1940

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2018

क्रमांक ई-1-15/2018/1/2.—भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 16/2/2016-EO (MM-I) दिनांक 13-07-2018 के तारतम्य में डॉ. रोहित यादव, भा.प्र.से. (सीजी : 2002), सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की सेवायें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को माननीय केन्द्रीय मंत्री, नागर विमानन विभाग (श्री सुरेश प्रभु) की निजी स्थापना में निज सचिव (संचालक स्तर) के पद पर नियुक्ति के लिए दिनांक 02-08-2018 (अपरान्ह) से कार्यमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. बाजपेयी, संयुक्त सचिव.

**आवास एवं पर्यावरण विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर**

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2018

क्रमांक एफ 7-6/2011/32/पार्ट-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र.-23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के दामाखेड़ा निवेश क्षेत्र की सीमाओं में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**रेजीना टोप्पो**, अपर सचिव.

**राजस्व विभाग**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर, दिनांक 25 अगस्त 2018

क्रमांक 13508/अ-82/2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	करिगांव प.ह.नं. 05	0.016	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता हसदेव बांगो नहर संभाग क्रमांक- 5, खरसिया, जिला-रायगढ़.	आमनदुला सब माईनर नं. 2, वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**नीरज कुमार बनसोड़**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं  
आपदा प्रबंधन विभाग**

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	घरघोड़ा	1.426	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़.	घरघोड़ा-तमनार सड़क चौड़ीकरण निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	नवापारा	1.719	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़.	घरघोड़ा-तमनार सड़क चौड़ीकरण निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	झरियापाली	2.098	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़.	घरघोड़ा-तमनार सड़क चौड़ीकरण निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	देवगढ़	2.158	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़.	घरघोड़ा-तमनार सड़क चौड़ीकरण निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2017-18.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	जरेकेला	1.050	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़.	घरघोड़ा-तमनार सड़क चौड़ीकरण निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2017-18.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	बासनपाली	2.672	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़.	घरघोड़ा-तमनार सड़क चौड़ीकरण निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं  
आपदा प्रबंधन विभाग**

बालोद, दिनांक 21 अगस्त 2018

क्रमांक/7008/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	बालोद	अमलीडीह	1.42	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व बालोद.	तरौद से दैहान बायपास मार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**सारांश मित्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़,  
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक 20/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—	
(क) जिला-रायगढ़	
(ख) तहसील-पुसौर	
(ग) नगर/ग्राम-राईतराई	
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.279 हेक्टेयर	
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
170	0.105
196	0.004
190	0.045

(1)	(2)
195/2	0.125
योग	04
	0.279

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत राईतराई माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक 21/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-राईतराई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.295 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
29/1	0.073
28/1	0.093
27/1	0.024
25	0.105
योग	04
	0.295

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत अमलीडीहा माइनर नहर हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक 24/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-बासनपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.323 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
189/1	0.230
187/11	0.093
योग	02
	0.323

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत रुचिदा माइनर नहर हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक 25/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़  
(ख) तहसील-पुसौर  
(ग) नगर/ग्राम-टेका  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.678 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
207/1,	
219/2, 8	0.045
262/2	
196/12, 196/13क	0.024
262/7	0.073
262/5	0.036
220/3	0.032
262/6	0.036
207/1,	
219/2, 6	0.105
262/2	
207/5	0.121
262/3	0.026
207/1,	
219/2, 7	0.073
262/2	
207/3	0.081
262/4	0.026
योग	12 0.678

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत तारापुर माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक 26/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़  
(ख) तहसील-पुसौर  
(ग) नगर/ग्राम-धनगांव  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.137 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
206/3क	0.061
214	0.028
231/12	0.012
447/4, 448/1ख	0.057
447/1ड़	0.129
463/8	0.121
465/491/1	0.016
464/2	0.032
218/1ख	0.028
206/2	0.008
212/1	0.113
447/2, 448/1क	0.057
447/7, 448/2ग	0.024
464/1	0.008
232/3	0.306
464/491/2	0.008
464/7क	0.097
233	0.016
213/2क	0.065
219/1	0.004
231/4	0.028
447/1च	0.097
464/3	0.073
464/4	0.020
442/5	0.121
442/4क	0.004
217	0.065
216	0.041
447/8, 448/2घ	0.057
464/5	0.073
463/2	0.121
465/2	0.0137
442/6	0.097

(1)	(2)	(1)	(2)
218/1क	0.013	494/1	0.024
		508/2	0.004
योग	34	510/1	0.012
	2.137	523/1	0.004
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत धनगांव माइनर-2 नहर हेतु.		346/2	0.012
		363	0.004
		364/1	0.049
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.		364/4	0.004
		519/4	0.173
		449/2	0.069
		451/1	0.016
रायगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2018		475/1	0.028
		477/2	0.004
क्रमांक 27/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		480/3	0.012
		491/5	0.081
		495/2	0.024
		508/4	0.016
		512/2	0.020
		330/2	0.073
		346/6	0.049
		480/1	0.141
		364/2	0.012
अनुसूची		364/5	0.032
		520/1	0.012
(1) भूमि का वर्णन-		450/5	0.036
(क) जिला-रायगढ़		451/2	0.036
(ख) तहसील-पुसौर		475/2	0.045
(ग) नगर/ग्राम-नावापारा		501/6	0.061
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.390 हेक्टेयर		513/3	0.041
		491/6	0.008
खसरा नम्बर	रकबा	508/1	0.053
	(हेक्टेयर में)	508/5	0.012
(1)	(2)	512/4	0.032
		330/3	0.133
330/1	0.073	346/8ख	0.024
331	0.065	496	0.073
364/1ग	0.036	514	0.057
512/1	0.057	365/1	0.061
364/3	0.041	369	0.012
365/2	0.049	450/3	0.049
476	0.045	452/4	0.008
478/1	0.101	475/3	0.032
452/6	0.020	478/2	0.012
477/1क	0.053	480/5	0.008
479	0.012	492	0.004
419/4	0.073	508/8	0.004

(1)	(2)
508/7	0.032
512/5	0.057
योग	60
	2.390

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत धनगांव माइनर-1 नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़  
(ख) तहसील-तमनार  
(ग) नगर/ग्राम-जरेकेला  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.456 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
578	0.057
577	0.089
579	0.069
580	0.073
581	0.168
योग	05
	0.456

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पाझर नाला पर पुलिया निर्माण हेतु भू-अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़  
(ख) तहसील-तमनार  
(ग) नगर/ग्राम-नवापारा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.387 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/2	0.008
149/2	0.057
152/1	0.012
1/3	0.032
150/1	0.036
81/2	0.032
81/1	0.032
150/2	0.077
79/1	0.061
149/1	0.040
152/1	0.012
योग	11
	0.387

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पाझर नाला पर पुलिया निर्माण हेतु भू-अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2018

## अनुसूची

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2017-2018.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़  
(ख) तहसील-धरमजयगढ़  
(ग) नगर/ग्राम-सिथरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.193 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
17/4	0.129
17/5 ख	0.056
20/3	0.008
योग	3
	0.193

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धरमजयगढ़-कोरबा-उरगा-हाटी मार्ग के कि.मी. 16/6 पर पहुंच मार्ग हेतु सेतु निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2017-2018.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## (1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़  
(ख) तहसील-धरमजयगढ़  
(ग) नगर/ग्राम-खड़गांव  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.338 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1288/5	0.161
1281/1	0.032
1288/4	0.097
1288/1	0.040
1280/3	0.008
योग	5
	0.338

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धरमजयगढ़-कोरबा-उरगा-हाटी मार्ग के कि.मी. 16/6 पर पहुंच मार्ग हेतु सेतु निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्रमांक 43/अ-82/2017-2018.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़  
(ख) तहसील-पुसौर  
(ग) नगर/ग्राम-मल्दा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.361 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/2	0.057
5/5	0.061
8/4	0.008
16/1	0.036
41/3	0.028
50/4	0.041
77/1, 91/2	0.161
4/3	0.016
7/2	0.077
9	0.101
36/1	0.073
41/4	0.016
51	0.024
4/4	0.137
8/2	0.057
15/1	0.065
36/3	0.016
45	0.045
52/2	0.097
5/4	0.069
8/3	0.008
15/2	0.045
41/6	0.030
46/1	0.089
76	0.004
योग	25 1.361

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के शारा वितरक नहर एवं मल्दा लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्रमांक 44/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़  
(ख) तहसील-पुसौर  
(ग) नगर/ग्राम-तुरंगा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.178 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1	0.105
8/3	0.073
योग	2 0.178

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के तेलीपाली वितरक नहर एवं तुरंगा माइनर लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्रमांक 47/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़  
(ख) तहसील-पुसौर  
(ग) नगर/ग्राम-बड़े हल्दी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.396 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
19/3	0.133

(1)	(2)
31/2, 32/1	0.083
33/15	0.097
36	0.105
71/1	0.008
72/1	0.045
151/2	0.073
153/6	0.012
158/7	0.012
161/3	0.045
30/1ख/2	0.020
19/8	0.076
31/4, 32/4	0.073
33/17	0.045
37/2	0.061
71/3ख/1	0.012
73	0.041
152/1क	0.243
152/4	0.004
158/8	0.028
162/1	0.045
21	0.097
32/5	0.081
35/1, 35/3	0.032
69/1	0.142
71/3क	0.004
74/1	0.029
152/3	0.085
152/8	0.146
160/2	0.041
165	0.089
30/1ख/1	0.020
33/16	0.146
35/2, 35/4	0.032
70	0.008
71/3ख/2	0.057
74/2	0.049
152/5	0.008
158/2	0.053
161/1	0.008
158/6	0.008
योग	41 2.396

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के तेलीपाली वितरक नहर एवं मल्दा लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्रमांक 48/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-पुसौर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.232 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

1872	0.041
1885	0.049
1873	0.028
1875/1	0.049
1875/2	0.008
1884/1	0.057
योग	6 0.232

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के तेलीपाली वितरक नहर एवं गुडू माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्रमांक 49/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़  
(ख) तहसील-पुसौर  
(ग) नगर/ग्राम-गुडू  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.908 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
135/6	0.020
182/4	0.028
409/25	0.041
409/27	0.020
141/7	0.036
135/7	0.049
149/2	0.020
409/29	0.085
409/17	0.020
21/1क	0.024
135/8	0.045
409/20	0.089
409/30	0.061
409/19	0.028
21/4	0.024
135/2	0.121
409/28	0.028
409/31	0.109
182/3	0.024
409/14	0.036
योग	20 0.908

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के तेलीपाली वितरक नहर एवं गुडू माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर,  
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2018

क्रमांक 10/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बिलासपुर  
(ख) तहसील-बिल्हा  
(ग) नगर/ग्राम-खम्हारडीह  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.159 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14	0.024
17	0.057
18/1	0.028
18/3	0.032
13/1	0.036
13/2	0.020
19/3	0.020
20	0.178
88/2	0.061
63/1	0.045
63/2	0.045
64	0.045
65/1	0.004
77/1,	0.020
78/1	0.032
80	0.105
77/2,	0.052
78/2	0.012
81/1	0.052
83/2	0.012
81/2	0.052

(1)	(2)	(1)	(2)
82,	0.109	250/1	0.032
83/1		8/2	0.032
57/1	0.004	12	0.012
57/4	0.004	8/1	0.113
94/4	0.012	7/2	0.045
86,	0.073	7/7	0.049
88/1		7/5	0.008
92	0.089	152/2	0.024
		7/4	0.008
योग	29	10/1	0.073
	1.159	27/1	0.061
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार		27/2	0.008
बैराज परियोजना के खम्हारडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.		28/1	0.032
		28/2	0.024
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी		29	0.053
(राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.		30/3	0.032
		34/1	0.024
		34/2	0.057
		30/2	0.061
बिलासपुर, दिनांक 11 अगस्त 2018		32	0.053
क्रमांक 53/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस		33/1,	0.142
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में		33/2	
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक		41/1	0.020
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और		43/1	0.053
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार		43/2	0.105
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा)		61/2	0.020
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि		62	0.073
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		65/5	0.040
		65/6	0.032
		75	0.053
		86	0.020
		82	0.016
		81	0.016
		80	0.081
		76/1	0.049
		76/2	0.049
		153/1	0.024
		144/3	0.045
		145/2	0.028
		154/4	0.028
		153/4	0.065
		152/1	0.032
		146/3	0.129
		147	0.045
		148	0.024
		149	0.036
		412	0.045
		413	0.259

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-तखतपुर

(ग) नगर/ग्राम-मोछ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.283 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

5

0.117

7/6

0.073

30/1

0.016

7/1

0.012

10/2

0.057

258/2

0.388

(1)	(2)	(1)	(2)
411/7	0.089	1441	0.166
411/8	0.077	650/1डू	0.999
587/4	0.012	1436/4	0.409
648	0.028	29	0.053
647/1	0.012	30/3	0.032
647/2	0.012		
647/3	0.012	योग	107 8.283
647/4	0.012		
646/1	0.016	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु.	
646/2	0.024	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
646/3	0.016		
636	0.028		
637	0.008		
638/1	0.040		
638/2	0.036		
638/3	0.012		
633	0.040	बिलासपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2018	
631	0.045		
597/3	0.012	क्रमांक 04/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-	
630/1	0.040		
597/1	0.053		
607	0.020		
604	0.032		
606	0.024		
605	0.049		
582	0.053		
579	0.053		
586	0.065		
584/1	0.020	अनुसूची	
583	0.081		
584/2	0.073	(1) भूमि का वर्णन-	
493	0.097	(क) जिला-बिलासपुर	
491/2	0.032	(ख) तहसील-बिल्हा	
764/1ख	0.413	(ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्रीडीह	
831/1	0.053	(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.790 हेक्टेयर	
831/2	0.065		
832/1	0.077	खसरा नम्बर	रकबा
832/2	0.081		(हेक्टेयर में)
841/2	0.109	(1)	(2)
1314/6	0.121	127/1	0.097
1314/5	0.243	127/2	0.016
1314/3	0.194	133/1	0.089
1314/9	0.202	134	0.040
1314/7	0.311	153/1	0.004
1315/2	0.138	152	0.057
1436/2	0.057	162	0.081
1437/3	0.214	160/1	0.004
1437/4	0.121		

(1)	(2)	(1)	(2)
161	0.057	85/1	0.040
160/2	0.036	85/2	0.008
151	0.049	85/3	0.021
166/2	0.057	84/1	0.016
167	0.073	95/1	0.032
114	0.008	95/5	0.081
113/3	0.053	95/8	0.032
115/2	0.057	95/18	0.012
113/2	0.012	95/15	0.008
योग	17	95/20	0.020
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु.		94/1	0.020
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.		94/2	0.040
		91/1	0.008
		94/3	0.016
		94/4	0.045
		97	0.061
		102/1,	
		102/2,	0.012
		102/3	
बिलासपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2018		105/1	0.040
क्रमांक 05/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		105/4	0.008
		105/5	0.032
		104/1	0.045
		104/2	0.016
		109/3	0.036
		118/37	0.024
		118/18	0.024
		118/1	0.101
		118/2	0.048
		116/1	0.048
		118/19	0.024
		118/16	0.057
		117/2	0.226
अनुसूची		योग	36
(1) भूमि का वर्णन—			1.309
(क) जिला-बिलासपुर			
(ख) तहसील-बिल्हा			
(ग) नगर/ग्राम-ऐटुलकापा			
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.309 हेक्टेयर			
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अमेरीकापा माइनर नहर निर्माण हेतु.	
79/1	0.024	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
87/1	0.028		
86	0.056		

बिलासपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2018

(1)

(2)

क्रमांक 11/अ-82/2017-18.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिल्हा

(ग) नगर/ग्राम-अमेरी अकबरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.239 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

49/3	0.036
49/4	0.024
48	0.028
52/2	0.045
50/1	0.004
52/1	0.057
52/3	0.016
52/4	0.012
38/2	0.008
54	0.057
60/1	0.061
60/2	0.049
60/3	0.068
61/1	0.008
61/2	0.089
63	0.077
62/2	0.008
64/2	0.032
64/3	0.032
64/4	0.020
64/5	0.016
69	0.065
68/1	0.045
71	0.057
73	0.053

योग

50

2.239

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अमेरी अकबरी माइनर, अमेरीकापा सब माइनर, अमेरी अकबरी सब माइनर 1, 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2018

क्रमांक 15/अ-82/2017-18.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन-		164/3,	0.073
(क) जिला-बिलासपुर		164/4	
(ख) तहसील-बिल्हा		165	0.121
(ग) नगर/ग्राम-उड़नताल		163/1	0.052
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.972 हेक्टेयर		163/7	0.024
		3	0.089
खसरा नम्बर	रकबा	4/1	0.028
	(हेक्टेयर में)	37/3	0.016
(1)	(2)	37/7	0.004
		38/3	0.045
10/2	0.012	31	0.008
129/1	0.267	38/2	0.125
129/2	0.134	38/1	0.057
130/4	0.004	43/4,	0.032
130/1	0.016	43/6	
128/1	0.154	43/5	0.073
128/2	0.316	58/1	0.008
133/1	0.117	68/1	0.008
133/2	0.057	57/13	0.175
4/2	0.016	57/10,	0.202
164/1,		57/11	
164/2	0.073		
164/10	0.097	योग	42 2.972
164/8	0.016	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार	
163/3	0.068	बैराज परियोजना के दगौरी माइनर नहर निर्माण हेतु.	
163/6	0.032	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी	
163/4	0.202	(राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
163/2	0.008		
43/10	0.073		
27/1,		छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
27/2	0.170	पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

### विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

प्रारूप-ख

[ नियम 5(1) देखिये ]

क्रमांक 114/बी 121/2017-18.—राज्य सरकार को लोक हित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं., तहसील डभरा, जिला जांजगीर-चांपा, छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम-लारा, प.ह.नं.-40, तहसील-पुसौर जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-सराईपाली, प.ह.नं. 33, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाए जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छ.ग. भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाये जाने के संबंध में प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप से आपेक्ष भेज सकेगा.

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. मे.)	
			खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	सराईपाली/33	173/3	0.085
योग कुल ख. नं.			1	0.085

### टीप :-

1. भूमि के नीचे लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय समक्ष प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

बी. पी. जायसवाल,  
सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय  
अधिकारी (रा.).

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 9th August 2018

No. 857/Confdl./2018/II-2-1/2017.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby, assigned additional charge of the Court as mentioned in Column No. (3) until further orders ;—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	Additional Charge (3)
2.	Smt. Neeta Yadav, Special Judge under S.C. and S.T. (P.A.) Act, Janjgir-Champa.	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).

By order of the High Court,  
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.